Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.471
Volume - 6, Issue - 1, January - 2023 Publication Date: 20/01/2023

DOIs:10.2018/SS/202301006 --:-- Research Paper / Article

मुद्रा योजना का आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव
(एक शोधात्मक अध्ययन)

[1] **डॉ. कमला फुलेरिया**
असिस्टेंट प्रोफेसर

[2] **जगत नारायण मौर्य**
शोध छात्र

एम.बी.पी.जी. कॉलेज, हल्द्वानी (नैनीताल)

Email - kamla.fuloria7@gmail.com
Email- jnmaurya96@gmail.com

सारांश : किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में व्यक्ति और समाज की विशेष हिस्सेदारी होती है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश का विकास होता है। किसी भी देश के विकास में जब तक हर व्यक्ति का योगदान नहीं होता तब तक वह देश अपने समस्त मानव संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, वह देश अपने विकास का लाभ अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में असमर्थ रहेगा। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा मुद्रा योजना की शुरुआत की गई ताकि गैर औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित ऐसी प्रतिभा जिनके पास सोच तो है लेकिन पूंजीगत अभाव के कारण वह सोच वास्तविक धरातल पर नहीं उतर पाता और हमारे भविष्य के सपनों का भारत जो एक समावेशी विकास की अवधारणा को चरितार्थ करना चाहता है पूंजी के अभाव में योगदान देने से वंचित हो जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा योजना की शुरुआत की गई है। जो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

मुख्य शब्द : मुद्रा योजना, गरीबी, सामाजिक, आर्थिक, दलितों, पिछड़ों एवं महिलाओं ।

1. प्रस्तावना :

वैश्विक पटल पर भारत की छवि आज के परिदृश्य में मजबूती से परिलक्षित होते हुए तथा विश्व गुरु के सपने के साथ आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान के सामने आंतरिक रुप में अनेक समस्याएं आज भी विद्यमान है। इन समस्याओं में गरीबी, बेरोजगारी, आय की असमानता, भ्रष्टाचार, लोगों के जीवन स्तर में कमी, परंपरागत सोच जो देश को आंतरिक रुप से आगे बढ़ाने में कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सोच और भविष्य के भारत निर्माण की रणनीति के तहत 8 अप्रैल 2015 को भारत के भविष्य निर्माण के लिए और आंतरिक समस्याओं से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। विभिन्न संसाधनों से युक्त भारत देश सदियों से रहा है, किंतु संसाधनों का उपयुक्त दोहन ना हो पाने के कारण गरीबी अपना स्थान बनाए रखती है। भारत देश में ऐसी कई परंपराएं हैं जो अन उत्पादक हैं और परंपराओं को निभाना आवश्यक है। अनुत्पादक कार्यों में अधिक धन व्यय होने कारण गरीबी व्याप्त रहती है। लोगों के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए यह एक सोचनीय विषय बन गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी (MICRO Units Development Refinance Agency) है। मुद्रा योजना भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है।

2. मुद्रा योजना के उद्देश्य :

- पुराने उद्योग का विस्तार करने के लिए एवं नया उद्यम प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा प्रदान की जाती है।
- लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए।
- रोजगार को बढ़ावा देने के लिए।
- लघु एवं कुटीर उद्योगों का विस्तार करने के लिए।
- छोटी इकाइयों को कम लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

- संस्थागत वित्त को बढ़ावा देना।
- रोजगार को बढ़ावा देना।
- उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- मुद्रा बैंक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सस्ती दरों पर आसान से लोन उपलब्ध कराएगा।

3. मुद्रा योजना के लाभ :

मुद्रा योजना के प्रमुख लाभ है उनका संक्षिप्त वर्णन अग्रलिखित है।

- इसके माध्यम से लोग अपने उद्योगों का आसानी से विस्तार कर सकते हैं और नए उद्योगों की स्थापना भी आसानी से कर सकते हैं।
- मुद्रा योजना से लोन लेते समय अपनी संपत्ति को गिरवी नहीं रखना पड़ता है अर्थात, जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना के माध्यम से सभी स्तर के व्यक्ति को कम शर्तों पर लोन दिया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है।
- इस योजना के माध्यम से स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना के माध्यम से गरीबी बेरोजगारी आय की असमानता जैसी आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलेगी।
- इस योजना के माध्यम से सामाजिक विषमता में कमी आएगी युवा आत्मनिर्भर बनेंगे।
- सकल उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी।
- इस योजना के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा।
- इस योजना के माध्यम से लोग आत्मनिर्भर होंगे, आर्थिक समृद्धि से चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, सामाजिक विस्तार होगा।

4. मुद्रा योजना का वर्गीकरण :

योजना के अंतर्गत तीन प्रकार का लोन लिया जाता है जो निम्नवत है-

मुद्रा योजना

शिशु लोन योजना | किशोर योजना | तरुण लोन योजना

शिशु लोन योजना– लोन के अंतर्गत 50000 तक का बिजनेस लोन दिया जाता है।

किशोर लोन योजना– किशोर लोन के अंतर्गत 50 हजार से ₹5 लाख तक का लोन दिया जाता है।

तरुण लोन योजना– तरुण लोन के अंतर्गत 5लाख से 10लाख तक का बिजनेस लोन दिया जाता है।

इस प्रकार से उपर्युक्त 3 तरीकों से मुद्रा योजना के माध्यम से लोन प्रदान किया जाता है, यह तीनों बिंदु मुद्रा योजना के महत्वपूर्ण आकर्षण है।

5. मुद्रा योजना की पात्रता :

- लोन लेने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए।
- मुद्रा लोन योजना के माध्यम से कृषि को छोड़कर कोई अन्य बिजनेस किया जा सकता है ।
- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के सभी उद्योग मुद्रा योजना के लिए पात्र हैं।

6. मुद्रा योजना के आर्थिक प्रभाव :

मुद्रा लोन योजना एक अलग वित्तीय संस्थान है। जिसका मुख्यालय मुंबई में है। व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, एन.बी.एफ.सी. के माध्यम से मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिया जाता है। इसके तहत ट्रांसपोर्ट, वेहिकल के लिए ऑटो, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर, टेंपो आदि व्यवसाय के लिए ऋण ले सकते हैं। व्यक्तिगत व्यवसाय जैसे- ब्यूटी पार्लर, जिम, बुटीक सेंटर खोलने, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, टेलर, ड्राई क्लीनर, फोटोकॉपी, फोटोग्राफी, कोरियर एजेंट, मशीन की दुकान, आदि इसके अलावा कोई कृषि प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग सेंट,र ढाबा खोलने के लिए, आचार, मुरब्बा बनाने, मिठाई की दुकान, बेकरी, पान की दुकान, जेली, जैम, पापड़, फास्ट फूड, स्टॉल लगाने या हैंडलूम, पावर लूम खोलने, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशु पालन, आदि के लिए ऋण ले सकते हैं।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (सांख्यिकी मंत्रालय भारत सरकार) 2018 के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 5.77 करोड़ लघु व्यवसाय की इकाइयां है। जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 12 करोड़ लोग कार्यरत हैं। इन सभी को मुद्रा योजना से सहायता मिल रही है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मुद्रा योजना के माध्यम से 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन किया गया है। सरकार ने मुद्रा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाने के लिए फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, पतंजलि, मेरुकैब, जोमैटो, ओला, अमूल, अमेजन, जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौता किया है।

मुद्रा योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन करते हुए नीति आयोग (National Institution for Transforming India) के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि अर्थव्यवस्था में लगभग 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन मुद्रा योजना के माध्यम से हुआ है। इस योजना के केंद्र में, सरकार ने महिलाओं, दलितों एवं अल्पसंख्यकों को समाहित किया है। मुद्रा योजना के माध्यम से बड़े अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। मुद्रा योजना वास्तव में सूक्ष्म वित्त एवं पुनर्वित्त उपलब्ध कराने का भी प्रयास कर रही है। इस योजना के जरिए छोटे छोटे कारोबार में लगे असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रभावशाली प्रयास किया जा रहा है और लोग मुद्रा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

भारत जैसे देश में जहां मुद्रा योजना रोजगार के विशेष अवसर पैदा कर रही है सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे देश जहां पर पूंजी का अभाव पाया जाता है मुद्रा योजना लोगों के लिए एक रामबाण औषधि के समान है। इस योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुद्रा योजना वित्तीय समावेशन हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। पूर्व में सरकार द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाए गए थे उसमें अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रभाव पड़ा, जिनका वित्तीय समावेशन के लिए कदम उठाए गए इस प्रकार हैं –

1–देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (19 जुलाई 1969)

2–लीड बैंक योजना (1969)

3–क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना (2 अक्टूबर 1975)

4–देश 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (15 अप्रैल 1980)

5–राष्ट्रीय पेंशन योजना (1 जनवरी 2004)

6–प्रधानमंत्री जन धन योजना (28 अगस्त 2014)

7–पेमेंट बैंकों की स्थापना (19 अगस्त 2015)

8–माइक्रोफाइनेंस बैंकों की स्थापना (16 सितंबर 2015)

9–प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (9 मई 2015)

10–प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना (9 मई 2015)

11–अटल पेंशन योजना (9 मई 2015)

इन्हीं योजनाओं में से मुद्रा योजना भी है, जो आर्थिक विकास का माध्यम बनी हुई है। ज्ञातव्य है कि भारत एक समय में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, आज भी सत्य है। अगर हम 1999 के आर्थिक उदारीकरण के बाद का जिक्र करें तो यह निकलता है की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में तेजी से वृद्धि हुई है जो इस प्रकार है।

तालिका

वर्ष	वृद्धि (वास्तविक प्रतिशत)
2021	9.2
2020	7.7
2019	4.50
2018	8.20
2017	6.76
2016	8.00
2015	7.30

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है की भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है इस प्रकार से भारत की उपलब्धि अच्छी है। सभी स्तर पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि मुद्रा योजना का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। डूइंग बिजनेस 2016 में भारत की राय 130 से 67 पायदान ऊपर उठकर डूइंग बिजनेस 2020 में 63 हो गया है।

उपर्युक्त तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है की मुद्रा योजना से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

7. सामाजिक प्रभाव :

किसी भी चीज के आर्थिक प्रभाव के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। मुद्रा योजना जोकि दलितों, पिछड़ों एवं महिलाओं से संबंधित लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी स्थिति को मुद्रा योजना के माध्यम से बल प्रदान किया जा रहा है जिससे लोगों को काम करने के अवसर मिल रहे हैं लोगों को अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक अवसर दिया गया जिससे आसान शर्तों पर लोन लेकर अपने कारोबार का विस्तार किया जा सके तथा नया उद्यम भी प्रारंभ किया जा सके। सड़कों पर ई-रिक्शा आजकल बहुत दिखाई देते हैं जो मुद्रा योजना का ही परिणाम है। जब किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो उसका सामाजिक स्तर भी सुधरता है अर्थात आर्थिक सुधार के पश्चात सामाजिक सुधार स्वयं होने लगता है।

भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है लेकिन मुद्रा योजना कृषि को उपेक्षित करती है मुझे लगता है कि यदि सरकार द्वारा योजना में कृषि को भी शामिल कर ले तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास को अधिक बल मिल सकेगा, इसके अतिरिक्त ब्याज की दर को थोड़ा और कम किया जाए एवं मुद्रा लोन देने वाली सभी संस्थाओं के ब्याज दर को एक सामान किया जाए। इससे लोगों को समझने में आसानी होती है तथा किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। रही बात सब्सिडी की तो इसकी भी आवश्यकता है जिससे लोगों को अपने उद्यम का विस्तार करने एवं प्रारंभ करने में कोई खतरा नहीं होता।

उपर्युक्त सभी बिंदुओं पर ध्यान आकर्षण करने से मुद्रा योजना को अधिकतम प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

8. निष्कर्ष :

उपर्युक्त तथ्यों पर ध्यानाकर्षण करने पर स्पष्ट होता है कि 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ की गई मुद्रा योजना अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को काफी बल प्रदान कर रही है। गांव कस्बों एवं शहरों के लोग आसान शर्तों पर लोन लेकर अपने उद्यम को प्रारंभ करने में सफल हो रहे हैं। एवं बंद किए उद्यम को नया विस्तार प्रदान कर रहे हैं। मुद्रा योजना (Mudra –Micro units development refinance Agency) के द्वारा समावेशी विकास संभव है। यह योजना बॉटम से लेकर शिखर तक अपना विस्तार प्रदान करने में सफलता प्राप्त कर रही है। नीति आयोग की तरह मुद्रा योजना का भी उद्देश्य है निचले स्तर से विकास को प्रारंभ करना। इस प्रकार मुद्रा योजना को सरकार द्वारा पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. प्रतियोगिता दर्पण, पेज नंबर-159, मार्च 2021
2. प्रतियोगिता दर्पण, पेज नंबर- 60, मार्च 2021
3. भारतीय अर्थव्यवस्था, लाल और लाल, प्रयाग पब्लिकेशन, प्रयागराज/
4. भारतीय अर्थव्यवस्था छठवां संस्करण–2021, दृष्टि (The vision)- (page n.–110)
5. https://www.hindiyojna.in/pradhan–mantri–mudra–loan–yojna–in–Hindi/
6. https://m. economic times.com/Hindi